प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 24 – 31 अक्तूबर 2016 मूल्य पांच रूपए

सीबीआई ने विजिलैन्स को सौंपी पर्यटन में दस करोड़ घपले की शिकायत

शिमला/शैल। प्रदेश पर्यटन निगम के पूर्व कर्मचारी नेता ओम प्रकाश गोयल एक लम्बे अरसे से निगम में करोडों के केन्द्रिय धन के दुरूपयोग और उसमें घपला होने के आरोप लगाते आ रहे हैं। यह आरोप लगाने की उन्होने बड़ी कीमत भी चुकायी है लेकिन निगम में फैले भ्रष्टाचार को बेनकाव करने के मुद्दे से पीछे नही हटे हैं। गोयल ने जो भी आरोप लगाये हैं उनके साथ आरटीआई के माध्यम से जुटाये दस्तवेजी प्रमाण भी साथ लगाये हैं। इन आरोपों को लेकर 2002 में प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। इस याचिका पर 13.3.2003 को फैसला आया था जिसमें निगम को कुछ निर्देश भी जारी हुए थे। गोयल का आरोप है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की भी अनुपालना नही की गयी है। गोयल के आरोपों पर निगम के निदेशक मण्डल और मुख्यमंत्री द्वारा भी कोई कारवाई न किये जाने के बाद ही उसने 20 मई 2016 को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राज्यपाल, शांता कुमार, आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह और राजन सुशांत के नाम शिकायत भेजी। इस शिकायत पर क्या कारवाई हुई है इसकी जानकारी भी आरटीआई के माध्यम से मांगी गयी है। 20 मई को भेजी शिकायत के बाद गोयल ने सितम्बर में कुछ और तथ्यों के साथ एक और शिकायत राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश, प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायधीश केन्द्रिय वित्त मंत्री, केन्द्र के केबिनेट सैक्रेटरी, सीएजी निदेशक सीबीआई और केन्द्रिय वित्त मंत्री केन्द्रिय पर्यटन सचिव को भेजी है। अब यह शिकायत सीबीआई ने प्रदेश विजिलैन्स को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक केन्द्रिय पर्यटन मन्त्रालय में भी इन आरापों को लेकर एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गयी है।

गोयल के आरोपों के मुताबिक 2001 से 2002 के बीच प्रबन्धन निदेशक ने होटल पीटरहॉफ में अपने मेहमानों को ठहराया जिनका खर्च निगम ने उठाया। इसी दौरान पर्यटन निगम ने कर्मचारियों का सी पी एफ जमा नही करवाया और उसके लिये निगम को 72 लाख का जुर्माना भरना पडा है। केन्द्र की सहयता से खड़ा पत्थर के होटल गिरी गंगा प्रौजैक्ट को 31 .12.2001 को 39.30 लाख में पूरा होकर इस्तेमाल में भी आ चुका होना दिखा दिया गया। जबकि जब 24.10.2005 को निगम के निदेशक मण्डल की वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रौजैक्ट को पूरा करने के निर्देश दिये जाते हैं। अन्त में 25.6.2006 को इसी प्रौजैक्ट को 1,38,84,076 रूपये में पूरा हुआ दिखवाया जाता है। इन आंकडों से प्रबन्धन की नीयत और नीति का खुलासा हो जाता है। जो प्रौजैक्ट 31. 12.2001 को 39.30 में पूरा हुआ दिखवाया जाता है वह 2006 में एक करोड़ से भी अधिक को पहुंच जाता है जिस पर क्यों और कैसे के सवाल उठना स्वाभाविक है। गोयल ने मार्च 2003 के उच्च न्यायालय के फैसले के निर्देशों पर अमल न होने पर अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर तत्कालीन सचिव पर्यटन अशोक ठाकुर ने अदालत में दायर जवाब में छः करोड तय कार्यो से अनयत्र खर्च होना स्वीकार किया है। सुंगरी प्रौजेक्ट को लेकर भी गंभीर आरोप लगाये गये हैं। इस प्रौजैक्ट के लिये 26396 को भारत सरकार से 46,11,600 रूपये स्वीकृति होने हैं तीन लाख प्रदेश सरकार देती है 31. 12.2009 को भारत सरकार को भेजे प्रमाण पत्रों में यह प्रौजेक्ट पूरा हो जाता है। लेकिन 2006 में जब मुख्यमंत्री यहां आते हैं तो इसे अधूरा पाते हैं। इसे पूरा करने के लिये इसको लोक निमार्ण को देने की बात करते हैं। इन निर्देशों पर लोक निमार्ण विभाग पर्यटन से मिल कर इसकी प्रक्रिया पूरी करते हैं और लोक निमार्ण विभाग इसको पूरा करने के लिये 76 लाख का अनुमान देते है।

इस तरह पर्यटन में जितने भी प्रौजेक्टों के लिये केन्द्र से पैसा आता है उसे प्राप्त करने के लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र और कमीशनिंग तक के सर्टीफिकेट भेज दिये जाते हैं और इनके आधार पर केन्द्र से सहायता की अन्तिम किशत भी प्राप्त कर ली

शेष पृष्ठ 2 पर.......................

CONFIDENTIAL

Central Bureau of Investigation
Industry • Impartiality • Integrity

Railway Board Building, The Mall Shimla.
Phone/Fax: 0177-2654110

1442(c)

No. /CA/91/2016/CBI/SML Dated: 24.10.2016

To
The Addl. Director General of Police,
SV & ACB, Khalini, Shimla.

Sub: Forwarding of Complaint-reg.

Sir,

Please find enclosed herewith a complaint made by one Sh. Om Prakash Goel, Advocate, r/o Saint Albans Cottage, Near Govt. Sr. Secondary School (Boys), Shimla against Unknown Officials of H.P. Tourism Development Corporation, Shimla, on the allegations of misutilization of funds to the tune of Rs. 10 crores approximately, received from Central Government on account of Central Grant for the construction of various projects in the state of Himachal Pradesh, for further necessary action please.

CBI, Shimla has not made any enquiry into the matter.

Yours faithfully,

Head of Branch, 14/10/16
CBI, Shimla.

Encl: As above.

Copy to:-

1. The Joint Secretary/Chief Vigilance Officer, Ministry of Tourism, Govt. of India, Room No. 119, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001, for information and necessary action please.
2. Sh. Om Prakash Goel, Advocate, Saint Albans Cottage, Near Govt. Sr. Secondary School (Boys), Shimla-171001, for information please.

क्रप्शन पर इस्तीफा मांगने के बाद वीरभद्र से मिलने IGMC पहुंचे नड्डा

शिमला/शैल। आगामी 201 7 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा सीएम अपने मामलों में उलझे हुए हैं जिससे सरकार के कामकाज में असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र से दिए जा रहे प्रोजेक्टों में जिस तरह की ढील बरती जा रही है उससे साफ है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में अपने मामले है ये प्रोजेक्ट नहीं। नड्डा ने ये सब संवाददाताओं की ओर से इस बावत पूछे सवालों के जवाब में कहा।

मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, मनी लांड्रिंग व आय से अधिक संपति के मामलों की जांच मोदी सरकार की एजेंसियां कर रही है। नड्डा ने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही है।

नड्डा राजधानी में 'मीट द प्रेस 'कार्यक्रम में प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया।

नड्डा ने इस मौके पर एक तरह से शक्ति परीक्षण भी दिखवाया। उनके साथ भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप, विधायक जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, सुरेश भारद्वाज और गोबिंद शर्मा के अलावा पूर्व विधायक नरेंद्र बरागटा, बीजेपी के प्रवक्ता गणेशदत व संदीपनी भारद्वाज भी इस मौके पर रहे। जयराम ठाकुर, सुरेश भारद्वाज और गोबिंद शर्मा नड्डा खेमे के माने जाते हैं। जबकि राजीव बिंदल, नरेंद्र बरागटा धूमल खेमे से हैं। लेकिन राजनीति में कौन कब पाला बदल ये कहा नहीं जा सकता। हर बार की तरह नड्डा ने इस बार भी कि वो प्रदेश की राजनीति में आएंगे ये सवाल टाल दिया। उन्होंने कहा उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। अभी वो केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

नडडा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वो केंद्र से मिलने वाले प्रोजेक्टों पर प्रदेश की ओर से की जाने वाली प्रक्रियाओं को तेजी से पूरी करे। उन्होंने केंद्रीय प्रोजेक्टों के

शेष पृष्ठ 2 पर.......................

स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद अपनाएं:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आयुर्वेद जीवन शैली है और जब इस प्रणाली में बदलाव किया जाता है तो इससे शरीर पर प्रभाव

पड़ता है और मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्होंने बेहतर एवं स्वस्थ जीवन यापन के लिये आयुर्वेद की इस पुरानी पारम्परिक प्रणाली को अपनाने की सलाह दी।

राज्यपाल कांगड़ा जिला के पपरोला में आयुर्वेद विभाग द्वारा राजीव गांधी राजकीय स्नात्कोत्तर कालेज एवं अस्पताल पपरोला के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं धनवंतरी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष का थीम 'मधुमेह के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये आयुर्वेद' निर्धारित किया गया है। यह विषय इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया गया है कि भारत विश्व के पहले तीन मधुमेह केन्द्रों में है तथा आयुर्वेद पारंपरिक हिन्दु चिकित्सा पद्धति है और इसका अथर्ववेद में उल्लेख है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का 28 अक्तूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने के निर्णय से यह साबित होता है कि हमारी अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीए एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, जिसकी यह हकदार है। मौजूदा एवं नित्य उभरती नई नई बीमारियों तथा आधुनिक दवा चिकित्सा पद्धति के कारण एंटीबायोटिक प्रतिरोधक तनाव उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को जन्मागत साधन के रूप में जाना जाता है और इसमें जीवन से मृत्यु तथा गर्भ से जन्म तक उपचार व्यवस्था है। यह जीवन विज्ञान है तथा बीमारियों के प्रबन्धन में दवाओं की भूमिका को काफी कम किया गया है तथा इसमें नित्य प्रति जीवन में शारीरिक गतिविधियों एवं स्वान–पान को महत्व दिया गया है।

राज्यपाल ने आयुर्वेद और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने विशेषकर युवाओं को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जंक फूड से परहेज की अपील की। उन्होंने विभाग को शिविर आयोजित करने का भी आग्रह किया जहां स्थानीय वैद्य को मंच उपलब्ध करवाया जाए तथा बहुमूल्य औषधीय पौधों की पहचान के लिये अलग से एक विभाग की स्थापना की जाए।

उन्होंने राज्य में आयुर्वेद के प्रोत्साहन के लिये आयुर्वेद मंत्री करण सिंह के प्रयासों की सराहना की।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने कालेज परिसर में धनवंतरी मंदिर में यज्ञ एवं पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर एक पौधा भी रोपा तथा पपरोला आयुर्वेदिक अस्पताल में नशा निवारण परामर्श क्लीनिक का लोकार्पण भी किया जो सप्ताह में दो बार खुली रहेगी।

राज्यपाल ने आयुर्वेद अस्पताल में ओपीडी का निरीक्षण भी किया तथा चिकित्सकों एवं मरीजों से संवाद किया। उन्होंने पंचकर्मा केन्द्र का दौरा भी किया और केन्द्र को सुदृढ़ करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये।

आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह ने कहा कि आयुर्वेद विभाग ने राज्य में आयुर्वेद के विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए है ताकि अधिक से अधिक लोग उपचार सुविधा प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य में समय समय पर विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिनके माध्यम से लोगों को आयुर्वेद उपचार की जानकारी एवं ज्ञान प्रदान करने के साथ–साथ मरीजों को नि:शुल्क उपचार एवं दवाईयां प्रदान की जा रही है।

उन्होंने विभाग के अधिकारियों तथा कॉलेज के चिकित्सकों से राज्य में आयुर्वेद के विकास के लिए एक दल के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में औषधीय जड़ी बुटियों का अपार भण्डार है जिसका आयुर्वेदिक दवाईयां बनाने में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने परिसर में नशा निवारण परामर्श केन्द्र के लोकार्पण के लिए राज्यपाल का आभार जताया और कहा कि विभाग राज्य में आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रचार के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा।

स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने कहा कि अधिकांश बीमारियां जीवनशैली के कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद इनकी रोकथाम एवं उपचार में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि सभी को इस भरोसेमंद पारम्पिक प्रणाली का संरक्षण करके इसे अपनाना चाहिए।

आयुर्वेद के निदेशक डा. एस.के. पुर्थी ने कहा कि राज्यपाल के निर्देशानुसार आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला में नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVIING TENDERS

Sealed item rate tenders are hereby invited on Form 6&8 by the Executive Engineer , Solan B& R Division H.P.PWD . Solan (H.P.) on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following work from the registered contractors of appropriate class enlisted in H.P.PWD whose registration stood renewed as per revised instructions and and also registered dealers under the Himachal Pradesh , General Sales Tax Act, 1968. The important dates of tender of tender are as under:-

1. **The Last date for receipt of application for tender forms.** — **21.11.2016 Up to 4:00 P.M.**
2. **The Last date of sale of Tender forms** — **22.11.2016 Up to 4:00 P.M.**
3. **The Last date of Receipt of Tender** — **23.11.2016 Up to 10:30 A.M.**
4. **The date of opening of Tender** — **23.11.2016 11:00 A.M.**

The tender shall be received Upto **10:30 A.M. on 23.11.2016** and will be opened on the same day at **11:00 AM**. In the presence of intending contractors or their authorized representatives who may like to be present. The tender forms can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours . The earnest money in the Shape of National Saving Certificate time Deposit /Account /Saving account in any of the Post Office in H.P. duly pledged in faovur of the Executive Engineer (B&R) Division H.P. PWD Solan must accompany with each tender conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Cost of form
1.	Construction of Galang Matiual raod km 0/0 to km 3/500)SH:- C/o Jeepable to 5/7 mtrs wide road in km 0/0 to 3/500, improvement of curve Grade in km 0/0 to 3/500 CD & soling in km 0/0 to RDs in km 0/0 to 1/500 (Under SCCP"	2,00,396/-	4,050/-	Two Months	350/-
2.	Special repair to heritage building of Govt. Senior Secondary School at Chail (SH:- Providing Paneling work	9,26,507/-	19,000/-	Two Months	350/-
3.	S/R to Govt P.G. Degree College at Solan (SH:- White washing , panting and distempering etc.	6,80,676/-	13,700/-	Two Months	350/-

TERMS AND CONDITIONS:-

1. The tender form will not be issued to those contractors whose performance has been found unsatisfactory.
2. The contactor must have executed similar work successfully during last 3 Years.
3. Application without earnest more will not be entertained
4. Contractor should have not more than two works in hands.

Adv. No.-2883/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल का त्रिलोकपुर मंदिर न्यास को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर मंदिर न्यास को भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को विशेषकर नवरात्रों में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने त्रिलोकपुर में अपने ठहराव के दौरान स्थानीय विधायक डॉ. राजीव बिन्दल तथा जिला प्रशासन से वार्तालाप किया।

हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने त्रिलोकपुर में राज्यपाल से भेंट की और उन्हें बूढ़ी दीवाली समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

इसके उपरांत, राज्यपाल ने हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीटयूट काला अम्ब द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। इस अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।

संस्थान के अध्यक्ष रजनीश बंसल ने राज्यपाल का स्वागत किया।

राज्य सामाजिक क्षेत्र में दो जन अभियान आरम्भ करेगा:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। जल स्रोतों, भांग की खेती को नष्ट करने तथा हिमाचल प्रदेश को बाह्य शौचमुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए गए अभियानों के सफल क्रियान्वयन के उपरांत राज्य सरकार ने अब सामाजिक क्षेत्र में दो बड़े जन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दिशा – निर्देशानुसार इन दो नये अभियानों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र विकलांग व्यक्तियों की पहचान करना तथा शिशु लिंग अनुपात पर नियंत्रण के लिए गर्भवती महिलाओं का शुरूआती पंजीकरण शामिल हैं।

राज्य में इन दो अभियानों के कार्यान्वयन के लिए कार्य – नीति तैयार करने के लिए मुख्य सचिव वी.सी. फारका की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्तों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार 3 दिसम्बर 2016 विश्व विकलांगता दिवस से पूर्व अधिक से अधिक विकलांगजनों की जांच पूरा करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, ताकि सभी पात्र पहली जनवरी, 2017 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करना आरम्भ कर सकें।

उन्होंने कहा कि विकलांग व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सम्बन्धित उपायुक्तों की निगरानी में राज्य भर में खंड स्तर पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में इन शिविरों के आयोजन के लिए पहले ही कार्य योजना तैयार कर ली है। आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता विकलांगता के लक्षण वाले व्यक्तियों को इन शिविरों में चिकित्सा जांच के लिए आने के लिए प्रेरित करेंगी।

फारका ने कहा कि सरकार गर्भवतियों के शीघ्र पंजीकरण के लिए एक अन्य अभियान भी आरम्भ करेगी और यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि सभी गर्भवती महिलाओं का 70 दिनों की अवधि के अंदर आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकरण हो। उन्होंने कहा कि परिणामों पर नियमित तौर पर नज़र रखी जाएगी तथा जन्म के समय लिंग अनुपात से सम्बद्ध सूचना प्राप्त करने के साथ–साथ जिला विशेष में 70 दिनों में कुल गर्भधारण एवं गर्भपात के आंकड़ों को भी हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राज्य में लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए यह अभियान बड़ा कारगर सिद्ध होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने इन अभियानों के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनाई गई रणनीति पर विस्तृत प्रकाश डाला।

कलाईमेट प्रूफिंग परियोजना के तहत सोसाईटियों का गठन जल्द होगा:भरमौरी

शिमला/शैल। भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जन जातीय व गैर जनजातीय पंचायतों में हिमाचल प्रदेश ईको सिस्टम कलाईमेट प्रूफिंग परियोजना के तहत सोसाईटियों के गठन के कार्य को जल्द ही पूरा किया जाएगा। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने धर्मशाला से आए वन विभाग के ईको सिस्टम कलाईमेट प्रूफिंग परियोजना के सलाहकार व सहायक अरण्यपाल को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मॉडल माईक्रो प्लान को पंचायतों में जल्द ही तैयार करें और ग्रामीण वन प्रबंधन सोसाईटियों के गठन में भी तेजी लाए ताकि इन क्षेत्रों में इस परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यो में जनसहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जर्मन सरकार व जर्मन बैंक (के. एफ. डब्ल्यू.) के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के दो जिलों कांगड़ा तथा चम्बा में इस परियोजना को अमलीजामा पहना रही है। जलवायु परिवर्तन से वन सम्पदा सिकुड़ती जा रही है और लोगो की आर्थिकी को मजबूत करने व वन सम्पदा व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के मकसद से इस परियोजना को लोगों के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि मॉडल माईक्रो प्लान के अन्तर्गत सोसाईटियों द्वारा सुक्ष्म योजनाएं बनाई जाएंगी जिसमें मुख्यत: चौडी पतीदार पौधों को रोपित करना, सूख रहे जल स्त्रोतों का जिर्णोद्धार, जड़ी बूटियों का तथा वन सम्पदा का संरक्षण सम्वर्धन व लोगों की वन सम्पदा का वैज्ञानिक तरिके से दोहन व आर्थिकी को मजबूत करना, पंजामूली का उन्मूलन, घासनियों के क्षेत्र को बढ़ाना, जंगलों को आग से बचाने के कार्यो को प्रभावशील तराके से क्रियान्वय करना शामिल है।

दूर-दराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा शीर्ष प्राथमिकता:वीरभद्र सिंह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के दूर-दराज डोडरा-क्वार क्षेत्र के जिस्कून और क्वार में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में विकास के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने व स्वास्थ्य एवं शिक्षण अधोसंरचना सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

गोसांग से जिस्कून तक सड़क की बदहाली पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभाग को इस बारे जांच के आदेश दिए। उन्होंने जिस्कून सड़क के निरीक्षण के बाद चिंता जताई तथा विभाग को छह महीने के भीतर सड़क का पुनर्निर्माण करने तथा सड़क किनारे नालियों की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा दूर-दराज क्षेत्रों की जीवन रेखा होती है और सड़कों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों को सर्दियों से पहले पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की है, जो युवाओं को कौशल एवं आजीविका के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ता योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत सामान्य श्रेणी के युवाओं को 1000 रुपये तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को 1500 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 500 शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की है, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने क्वार में कर्मचारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। उन्होंने डोडरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्वार को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने में भी घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिस्कून और अस्पताल के लिए भवन निर्माण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्वार में उप-अग्निशमन केन्द्र की घोषणा भी की। उन्होंने धंधारवाड़ी में मिनी बस स्टैंड की भी घोषणा की।

उन्होंने डोडरा-क्वार सड़क को अगले वर्ष पक्का करने की भी घोषणा की और इस बारे सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने जिस्कून से झाखा के लिए सड़क निर्माण, फोटोडवार से क्वार के लिए एम्बुलेंस सड़क निर्माण, क्वार हेलिपैड से चायधार सड़क को पक्का करने की भी घोषणा की। उन्होंने जाखा में हेलिपैड निर्माण की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला धंधारवाड़ी-II, डोडरा की पुजारली और भावटा को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोडरा में खेल मैदान के निर्माण की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने जिस्कून में पशु औषधालय डोडरा-क्वार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपमण्डल खोलने के लिए सर्वेक्षण करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बैंक शाखा खोलने की मांग पर आश्वासन दिया कि यहां पर किसी भी बैंक की शाखा खोलने का मामला सम्बन्धित अधिकारियों से उठाया जाएगा।

सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए तैयार किया जाएगा रोडमेप

शिमला/शैल। वर्तमान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, सोशल एवं पारम्परिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने के लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग वृहद रोडमेप तैयार किया जाएगा।

यह जानकारी सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की वर्तमान प्रदेश सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेश में व्यापक प्रचार अभियान आरम्भ करने की रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। यह विशेष प्रचार अभियान प्रदेश सरकार के 25 दिसम्बर, 2016 को चार साल पूरा होने से एक सप्ताह पूर्व आरम्भ किया जाएगा, जिसमें लोगों को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों बारे जागरूक किया जाएगा।

अग्निहोत्री ने कहा कि विशेष प्रचार अभियान मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता से आरम्भ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल के सदस्य सम्बन्धित जिलों में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पब्लिसिटी स्टाल स्थापित किए जाएंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की उपलब्धियों का प्रचार लोक सांस्कृतिक दलों द्वारा पारम्परिक वेशभूषा के साथ शिमला शहर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विभाग की नई पहल होगी, जिससे पर्यटकों को भी आकर्षित किया जाएगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए मोबाईल, पब्लिसिटी वाहन, एलईडी स्क्रीन, ध्वनि प्रसार प्रणाली, प्रदर्शनी पैनल इत्यादि भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पब्लिसिटी वाहन प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संचार का एक प्रभावी अंग है।

अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग सफलता की कहानियों पर आधारित लघु फिल्म व वृत्त चित्र भी तैयार करेगा और यह मोबाइल वैनों व स्थानीय केवल आप्रेटरों के माध्यम से दर्शाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों पर रेडियो जिंगल तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए निश्चित स्थानों पर इलैक्ट्रॉनिक न्यूज डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। सरकार की उपलब्धियों पर आधारित नियमित फीचर भी जारी किए जाएंगे।

सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का प्रचार करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को पारम्परिक मीडिया जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विकासात्मक सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए गीत तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते होर्डिंग्स भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स आकर्षण सूचनात्मक और लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले होने चाहिए।

अग्निहोत्री ने कहा कि विशेष प्रचार अभियान में संचार के सभी साधनों का उपयोग सुनिश्चित बनाया जाएगा ताकि सरकार की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकार के चार वर्ष पूरा होने पर एक विशाल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए शीघ्र ही जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।

अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सभी क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग को प्रचार के सभी नवीनतम उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे व सही प्रकार से कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्र में वाहन भी प्रदान किए जाएंगे।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक आर.एस. नेगी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा विभाग की गतिविधियों बारे अवगत करवाया।

राज्य सरकार ने बढ़ाई शौर्य पुरस्कार की वार्षिकी की दर

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने शौर्य पुरस्कारों की वार्षिकी की दर को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि कीर्तिचक्र विजेताओं को प्रदान की जाने वाली वार्षिकी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ लाख रुपये, वीरचक्र तथा शौर्यचक्र की वार्षिकी को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, सेना मैडल तथा मेंशन-इन-डिस्पैच को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर प्रत्येक को 10 हजार रुपये, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, उत्तम युद्ध सेवा मैडल, युद्ध सेवा मैडल, विशिष्ठ सेवा मैडल की वार्षिकी को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रत्येक परम विशिष्ठ सेवा मैडल की वार्षिकी को 5400 रुपये से बढ़ाकर 10,800, अति विशिष्ठ सेवा मैडल की वार्षिकी को 4800 रुपये से बढ़ाकर 9600 रुपये तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सेना मैडल की वार्षिकी को बढ़ाकर 8000 रुपये किया गया है।

भरमौरी ने सुनी भरमौर के लोगो की समस्याएं

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी 7 अक्तूबर से विधान सभा क्षेत्र भरमौर-पांगी के प्रवास पर है। भरमौर में उन्होंने विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनी और मौजूदा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों के कार्यों के निष्पादन के आदेश दिए। वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भरमौर क्षेत्र में कार्य करने की सीमित अवधि के कारण विकास कार्यों में तेजी लाएं ताकि लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। इस अवसर पर जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य भजन सिंह ठाकुर, निदेशक मण्डल वन्यप्राणी के मनोनित सदस्य कमलेश ठाकुर, बी. ओ. डी., वन विकास के सदस्य संजय ठाकुर भी मौजुद रहे।

महासू सहभागिकता प्रकोष्ठ ने दी सरकार को आन्दोलन की चेतावनी

शिमला/शैल। संजय शर्मा महासू सहभागिकता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं नारकण्डा सरकारी तहसील यूनियन के अध्यक्ष तथा महासू साहकारिता प्रकोष्ठ के महामंत्री टेक सिंह ने कहा है कि यह दुभार्ग्यपूर्ण है कि जो संस्थान सरकार के अधीन काम कर रहे वह भी किसानों से ठगी एवं धोखा करने में लगे है जो चिन्ताजनक हैं इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ने के बजाय घटेगी और नुकसान अलग से होगा।

संजय शर्मा एवं टेक चंद ने संयुक्त ब्यान में कहा है कि किसानों को बढ़िया खाद मुहैया करवाई जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार दलालों के प्रभाव में आकर किसानों को दलालों की मार्फत लूटना चाहती है। अगर फैसला बदला न गया तो यह समझा जायेगा कि सरकार भी हिमफैड के साथ दलाली में मिली हुई है और यह चीन को फायदे के साथ-साथ दलालों के फायदे की भी चिन्ता है न कि हिमाचल के किसानों की।

किसान अच्छी खाद खरीदने में सक्षम है वशर्ते कि उसकी गुणवता अच्छी हो संजय शर्मा एवं टेक चंद ने चेताया कि यदि फैसला न बदला गया और चीन की ही खाद बेची गई तो पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान के साथ-साथ आन्दोलन की भी तैयारी की जायेगी।

जो चीज विकार को मिटा सके, राग–द्वेष को कम कर सके, जिस चीज के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे वही धर्म की शिक्षा है.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

कर्मचारी भर्ती पर केन्द्र के फैसले पर अमल क्यो नही

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ अरसे से मन्त्रीमण्डल की हर बैठक मे विभिन्न सरकारी विभागों में खाली चले आ रहे पदों को भरने का निर्णय लेने का क्रम शुरू किया है। इस क्रम में अबतक हजारों की संख्या में खाली पदो को भरने के आदेश जारी हो चुके हैं। खाली पदों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में नये पदों का सृजन भी किया गया है। सरकार में किसी भी पद को भरने के लिये एक तय प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें राज्य का लोक सेवा आयोग प्रथम और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदों को भरने की जिम्मेदारी निभाता है। गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिकृत है। इन दोनों अदारों के अतिरिक्त और कोई कर्मचारी भर्ती के लिये अधिकृत नहीं है। इन अदारों से हटकर केवल आऊट सोर्सिंग के नाम पर ही भर्ती की जा सकती है और कई विभागों में यह आऊट सोर्सिंग चल रही है। तय प्रक्रिया के तहत किसी भी पद को भरने के लिये कम से कम चार से पांच माह तक का समय लग जाता है। जहां कहीं पहले लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया रहेगी वहां पर यह समय एक वर्ष तक का भी हो सकता है। इस प्रक्रिया से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पद अब सृजित और विज्ञापित होंगे उन्हें भरने के लिये कितना समय लग जायेगा।

हिमाचल में रोजगार के नाम पर सबसे बड़ा अदारा सरकार और सरकारी नौकरी ही है। सरकारी नौकरी में भर्ती के लिये प्रदेश में 1993 से 1998 के बीच चिटों पर भर्ती का कांड हो चुका है। इसमें सारी तय प्रक्रियाओं को अंगूठा दिखाते हुए हजारों की संख्या में चिटों पर भर्तीयां की गई थी। इन भर्तीयों को लेकर बिठाई गयी जांच रिपोर्टो पर ईमानदारी से कारवाई की जाती तो यहां पर हरियाणा के ओमप्रकाश चौटाला की तर्ज पर कई लोगों की गिरफ्तारी हो जाती। चिटों पर भर्ती कांड के बाद हमीरपुर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कांड हुआ जिसमें अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर गिरफ्तारीयां हुई है। इन दोनों प्रकरणों से यह प्रमाणित होता है कि हिमाचल में रोजगार का सबसे बड़ा साधन सरकार ही है और उसमें हर बार घपला होने की संभावना बराबर बनी रहती है। प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों का आंकडा लाखों में है और इसी कारण जिन क्लास फोर के पदों के लिये वांछित योग्यता मैट्रिक या प्लस टू रहती हैं वहां पर इनके लिये एम ए और पी एच डी तक के आवेदन आ रहे हैं। उद्योग विभाग में तो अधिकारिक तौर पर यह सामने आ चुका है कि क्लास फोर के लिये बी ए, एम ए और पीएचडी के लिये अधिमान देने के लिये अलग अंक रखे गये थे। पटवारियों और सहकारी बैंक की परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं।

प्रदेश में 2017 में विधान सभा चुनाव होने है। लेकिन यह चुनाव तय समय से पहले भी हो सकते है इसकी संभावनाएं भी बराबर बनी हुई हैं बल्कि जिस ढंग से मुख्यमन्त्री ने पिछले दिनों प्रदेश का तूफानी दौरा किया है और सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया उससे इन अटकलों को और बल मिला है। इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि इस समय जो नौकरियों का पिटारा खोला गया है वह केवल विधानसभा चुनावों को सामने रखकर ही किया जा रहा है। इससे सरकार की नीयत और नीति को लेकर भी यह सवाल उठते है कि इस समय हजारों की संख्या में जो पदों को भरने की स्थिति आयी है क्या यह पद अभी खाली हुए या पिछले तीन वर्षो से खाली चले आ रहे थे? जो पद अब सृजित किये गये हैं उनके बिना पहले कैसे काम चल रहा था? इसलिये इन पदों के भरे जाने पर अभी भी सन्देह है क्योंकि यदि किसी कारण से विधानसभा चुनावों की स्थिति आ जाती है तो यह सारी प्रक्रिया आचार संहिता के नाम पर रूक जायेगी। ऐसे में यदि सरकार इन पदों को भरने के लिये गंभीर और ईमानदार है तो तुरन्त प्रभाव से केन्द्र की तर्ज पर तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों को भरने के लिये परीक्षा और साक्षाकार को समाप्त करके केवल शैक्षणिक योग्यता के अंको के आधार पर ही चयन किया जाना चाहिये। प्रदेश सरकार केन्द्र के इस फैंसले को अपनाने से टाल मटोल करती आ रही है और इसी से उसकी नीयत पर सन्देह पैदा हो जाता है।

युवा सशक्तिकरण के लिये कौशल उन्नयन

प्रदेश सरकार राज्य के 18 से 35 वर्ष आयु के सभी युवाओं के ज्ञान अर्जन तथा जीवन पर्यन्त रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिये प्रतिबद्ध है। इससे न केवल राज्य का उत्पादक कार्यबल बढ़ेगा, बल्कि युवाओं को लाभकारी आजीविका तथा रोजगार के अवसर प्रदान कर राज्य का कौशल घाटा पाटने में भी मदद मिलेगी।

राज्य में युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार सुनिश्चित बनाने के लिये प्रशिक्षित पेशेवरों का एक पूल तैयार करने के लिये राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की है। निगम द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को समेकित एवं इकट्ठा किया गया। राज्य सरकार ने अगले कुछ वर्षो के दौरान लगभग 52000 युवाओं को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की है। प्रशिक्षणार्थियों को औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही पाठयक्रमों में वैतनिक अथवा स्व–रोजगार के माध्यम से आजीवन आजीविका के अवसर सृजित करने के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार एशियन विकास बैंक तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निजी क्षेत्र संगठनों के साथ संजीदगी से कार्य करके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम प्रक्रिया तथा गुणात्मक प्रशिक्षण अधोसंरचना तैयार कर रही है। निगम ने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ सहभागिता की है। इन प्रशिक्षण प्रदाताओं ने आवंटित जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं और चयनित पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

सरकार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित बनाएगी। इससे न केवल बड़ी संख्या में युवाओं को गुणात्मक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुलभ होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रमाणीकरण का कार्य राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, क्षेत्रीय कौशल परिषद् तथा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

इस वर्ष नवम्बर माह से पायलट आधार पर राज्य के 1080 युवाओं को प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। ऑटोमोबाईल, फर्नीचर, स्वास्थ्य चिकित्सा, आतिथ्य सत्कार, सूचना प्रोद्योगिकी, जीव विज्ञान, परचून एवं टैक्सटाईल जैसे आठ क्षेत्रों में 13 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण स्नात्तकों, स्कूल से उतीर्ण अथवा स्कूल छोड़ चुके युवाओं, महिलाओं, असंगठित क्षेत्रों के अर्धकुशल व्यावसायी तथा विशेष क्षमता वाले लोगों के लिये उपलब्ध होगा। प्रशिक्षण गैर आवासीय आधार पर प्रदान किया जाएगा तथा प्रशिक्षण, 40 किलोमीटर अथवा इससे अधिक दूरी की यात्रा के लिये और आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति में रहने व खाने का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार संबंधित अग्रणी उद्योगों में प्रशिक्षणार्थियों की प्लेसमेंट अथवा स्थापन में भी सहायता करेगी।

प्रशिक्षण के स्तर एवं अध्ययन सूची को संबधित क्षेत्रीय कौशल परिषद द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर तैयार किया गया है। पाठयक्रम सूची में साफ्ट स्किलज, कंप्यूटर का ज्ञान, वित्तीय ज्ञान तथा उद्यमिता विकास भी शामिल होंगे।

12वीं कक्षा पास 90 युवाओं को ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑटोमोटिव क्षेत्र में 10वीं पास 180 युवाओं को इसी क्षेत्र में फीटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि लगभग तीन माह की होगी। कुल 120 युवाओं को लकड़ी के फर्नीचर में बढ़ई एवं फीटर के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तीन माह के प्रशिक्षण के लिये किसी प्रकार की औपचारिक शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है तथा प्रशिक्षण मण्डी में प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल में सामान्य ड्यूटि सहायक का प्रशिक्षण कांगड़ा में प्रदान किया जाएगा जिसमें पांचवी पास 30 युवाओं को चार माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार, 180 युवाओं को आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में खाद्य एवं पेय पदार्थ सहयोगी तथा अतिथ्य व स्वागत अधिकारी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कम से कम 10वीं पास युवाओं को कुल्लू में प्रदान किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवा उद्योग के देशव्यापी विस्तार से युवाओं को रोजगार के बड़े अवसरों सहित इन क्षेत्रों में अनेक नये उद्यमी प्रवेश कर रहे हैं। इस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिये शिमला में 90 युवाओं को वाइस आप्रेटर तथा डाटा एन्ट्री आप्रेटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, फार्मेसी/मैकेनिकल एवं कैमिकल इंजीनियरिंग/बी. फार्मेसी/बीएससी/एमएससी/एम. फार्मेसी में डिप्लोमा धारक 60 युवाओं को जीव विज्ञान क्षेत्र में बतौर प्रोडक्शन कैमिस्ट प्रशिक्षित किया जाएगा। चार माह से अधिक अवधि का यह प्रशिक्षण बद्दी में प्रदान किया जाएगा। कपड़ा उद्योग क्षेत्र एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की अपार संभावना है। इसके लिये सोलन जिले के बद्दी में कपड़ा उद्योग क्षेत्र में पाचंवीं पास 120 युवाओं को रिंग फेम डॉफर्ज के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कांगड़ा में 12वीं पास 210 युवाओं को परचून क्षेत्र में बतौर रिटेल सेल्ज एसोसियेट तथा सेल्ज एसोसियेट का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्य के इच्छुक युवा उम्मीदवार, जो उपरोक्त में से किसी में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हों, www.hpkvn.nic.in पर लॉग–ऑन कर इस महत्वकांक्षी, निःशुल्क तथा रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सौर शक्ति के माध्यम से ऊर्जा निर्धनता होगी दूर

सस्ती सौर लालटेनों में ग्रामीण भारत के कई क्षेत्रों में रोशनी हेतु प्रयुक्त जीवाश्म आधारित प्रदूषणकारी कैरोसीन का स्थान लेने की सम्भावना निहित है

अनुमान है कि देश के 18000 सुदूरवर्ती गाँवों में विद्युत की सुविधा नहीं पहुँच पाई है। इस समस्या के समाधान का परंपरागत तरीका केंद्रीयकृत वैद्युत ग्रिडों के माध्यम से इन गाँवों को जोड़ना है। यद्यपि यह समाधान न केवल पूँजी प्रधान है और अधिक खर्चीला है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी महंगा है क्योंकि इसके लिए विद्युत का संचरण पारंपरिक वैद्युत उत्पादन स्टेशनों से होता है।

इसकी बजाय छोटे स्तर पर विकेन्द्रित ऑफ – ग्रिड समाधान, विशेषकर सौर ऊर्जा का स्थापन, विश्वसनीय वैद्युत आपूर्ति के साथ आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

पांडुराम हेगड़े

यह ऑफ – ग्रिड सौर शक्ति प्रणाली क्या होती है एवं कैसे कार्य करती है?

सौर शक्ति में प्रदूषण फैलाये बिना वैद्युत उत्पादन की अपरिमित क्षमता है और यह स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख स्त्रोतों में से एक है एवं जलते हुए जीवाश्म ईंधन का विकल्प है। आबद्ध सौर विद्युत प्लांट एवं छत पर स्थित सौर प्रणालियों का स्थापन अनिवार्यत: मौजूदा देशव्यापी वैद्युत ग्रिडों से जोड़ने के लिए है। इसके विपरीत ऑफ – ग्रिड प्रणालियां वह होती हैं जो विकेन्द्रित घर में अथवा गांवों के स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती हैं।

व्यक्तिगत रूप से घरों में

विद्युत उत्पादन हेतु सोलर पैनल समेत घर के लिए सौर प्रणालियां उनको जोड़ने का आसान तरीका है जो बिजली के कनेक्शन से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत में बेतहाशा कटौती की स्थिति में यह एक विकल्प भी हो सकता है।

सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना एक अन्य ऑफ – ग्रिड वैद्युत पहल है जिसका देश के विभिन्न हिस्सों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। हांलाकि इसमें शुरूआती पूँजी व्यय अधिक है, किन्तु आगामी वर्षों में सस्ती और बेरोकटोक विद्युत आपूर्ति और रखरखाव पर कम खर्च से यह मालिक को भुगतान की वापसी कर देती है। इसमें कृषक समुदाय को अन्न सुरक्षा के साथ साथ विद्युत संकट के समाधान का मुद्दा है।

सस्ती सौर लालटेनों में ग्रामीण भारत के कई क्षेत्रों में रोशनी हेतु प्रयुक्त किये जा रहे जीवाश्म आधारित प्रदूषणकारी कैरोसीन का स्थान लेने की सम्भावना निहित है। इसी प्रकार बैटरी लगी माइक्रो – ग्रिड बिजली का संग्रहण कर सकती हैं। इसके माध्यम से मोबाइल रिचार्ज किये जा सकते हैं और सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित संचार प्रणालियों को विद्युत की आपूर्ति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सौर चालित प्रशीतन प्रणालियों में जीवनरक्षक दवाएं रखी जा सकती हैं।

कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक प्रयोग में सौर चालित सुखाने वाले यन्त्र एवं पानी गर्म करने वाली प्रणालियां पहले ही इस्तेमाल में हैं और मौजूदा सौर मिशन के तहत इनको सहायता दिए जाने की जरुरत है। इन प्रणालियों से पारंपरिक ऊर्जा की खपत में कमी होती है जिससे ऊर्जा की बचत होती है।

सौर ऊर्जा की महत्ता को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सौर मिशन की क्षमता 22 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट तक करने की अनुमति प्रदान की है। भारत सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 40 गीगावाट के छत आधारित सौर वैद्युत उत्पादन एवं 60 गीगावाट के मध्यम विकेन्द्रित ऑफ – ग्रिड कनेक्शन की एक विस्तृत रूपरेखा बनायी है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 60 हजार करोड़ का निवेश किया जा रहा है जो सौर बाजार का लाभ उठाने वाले उद्यमियों को अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा। भारत विश्व का अकेला देश है जिसने सौर ऊर्जा के इस लक्ष्य के संधान के लिए विश्व बैंक से एक बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित किये हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा के वैश्विक नेता भारत में निवेश करना चाहते हैं। घर से संचालित सौर प्रणालियों के स्थापना के लिए पहले ही 40 कंपनियां आगे आई हैं। इन प्रणालियों के लिए बड़ा शुरूआती व्यय वित्तीय संस्थानों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को, वहन करना पड़ेगा। इस बारे में नीतिगत मदद से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्पाद खरीदने के इच्छुक विशाल ग्राहक आधार के जरिये ऑफ – ग्रिड सौर बाजार की निरंतर वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। किसी अन्य सामान की भांति लोग आने वाले वर्षों में मिलने वाली सुनिश्चित सेवाओं के साथ सौर उत्पाद खरीदने के इच्छुक होंगे।

ऑफ – ग्रिड सौर प्रणालियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रखरखाव एवं सेवाएं मुहैया कराने के लिए कुशल श्रमशक्ति एवं तकनीशियनों की आवश्यकता होगी। भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए कौशल विकास कार्यक्रम को ग्रामीण युवाओं की क्षमताओं से जोड़ने की जरुरत है ताकि आजीविका के अवसर एवं निरंतर आय के स्त्रोत मुहैया हो पाएं। सौर ऊर्जा से जुड़े कार्यों के लिए तकनीशियनों के रूप में एक मिलियन हरित – रोजगारों का निर्माण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर देगा।

ऊर्जा अभिगम्यता सदी के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति से मजबूती से जुड़ा है। ऊर्जा के आधुनिक स्वरूपों तक पहुंच का अभाव ऊर्जा निर्धनता लाता है। भारत में 360 मिलियन लोग ग्रिड संपर्क के बिना जीवनयापन करते हैं और ऊर्जा निर्धनता से ग्रसित रहते हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू सौर मिशन में जनसमुदाय के इस भाग को ऊर्जा निर्धनता से बाहर निकालने एवं नवीकरणीय ऊर्जा का नियमित और स्वच्छ स्त्रोत प्रदान करने की क्षमता है।

पसूका

BCCI पर लोढ़ा पैनल नियुक्त करेगा ऑडिटर, ठेकों की होगी जांच

शिमला/शैल। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के हाथ से दुनिया की सबसे अमीर संस्था बीसीसीआई का कारोबार फिसलने के कगार पर आ गया है। पूरी तरह नहीं तो कई मामले उनके हाथ से निकलने जा रहें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में कहा है कि जस्टिस लोढ़ा पैनल एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा और बीसीसीआई

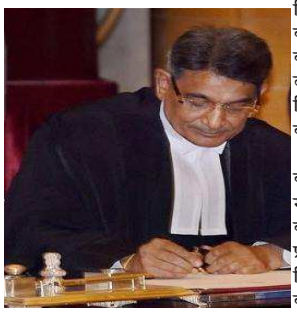

के तमाम ठेकों की जांच करेगा।

बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से इंकार कर दिया था व कहा था कि लोढ़ा पैनल की कई सिफारिशें लागू कर दी है लेकिन बाकी सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की हामी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कई शक्तियां लोढ़ा पैनल को दी हैं। ये बीसीसीआई के अब तक के धंधों पर चादर डालने के प्रयासों के लिए बुरा साबित हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को तीन दिसंबर तक लोढ़ा पैनल की सिफारिशें लागू करने का हलफनाम दायर करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच दिसबंर को रखी गई है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से राज्य क्रिकेट एसोसिएशनों को फंड आवंटित करने पर भी रोक लगा दी है। यह रोक तब तक रहेगी जब राज्य की क्रिकेट एसोसिएशनें लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करने के बारे को लेकर अदालत में हलफनामा दायर न कर दें। बीसीसीआई के लिए सबसे बुरा ये हुआ कि अब काट्रेक्ट लोढ़ा पैनल ही तय करेगा।

याद रहे कि अगस्त में कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिक्स क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने बीसीसीआई का कामकाज देखने के लिए प्रशासक नियुक्त करने की सिफारिश की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लोढ़ा पैनल को ही स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने की जिम्मेदारी दे दी।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि बीसीसीआई हर पहलू पर विचार करेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में वित मंत्री अरुण जेटली के बेहद करीबी है।

पिछले डेढ दशकों में भद्र लोगों का ये खेल सेक्स, सटटे व ड्रग्ज को लेकर बदनाम हुआ है। अब देखना है कि बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट सुधार करवा पाता है या नहीं।

हजारों अवैध भवनों को नियमित करने वाले बिल पर अभी साइन नहीं किए गवर्नर ने,मंत्री,अफसर हड़काए

शिमला/शैल। चुनावी साल होने की वजह से प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार की गले का फांस बने हजारों अवैध भवनों को नियमित करने वाले बिल पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साइन नहीं किए है। पिछले सत्र में सरकार ने इस बिल को विधानसभा से पास करवा कर राज्यपाल को साइन करने भेजा था।

लेकिन अभी तक राज्यपाल ने इस पर साइन नहीं किए तो सरकार ने तरकीब निकाली और बिल पर चर्चा कराने का रास्ता निकाला। प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना (संशोधान) विधेयक, 2016 पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ चर्चा करने के लिए खुद शहरी मंत्री सुधीर शर्मा ने पहल की व राज्यपाल के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गवर्नर ने मंत्री व अफसरों को अपने स्टाइल में हड़काया व निर्देश दिए कि अवैध निर्माण न होने पाए।

हालांकि बीते भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में कुछ नेता गवर्नर से मिला व इस बिल को साइन करने का आग्रह किया। गवर्नर को केंद्र की मोदी सरकार ने नियुक्त कर रखा है व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में अगर गवर्नर ने इस बिल को साइन नहीं किया तो आगामी विधानसभा में भाजपा को राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है।

प्रदेश में अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। बैठक में सुधीर शर्मा के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसीपी मनीषा नंदा, निदेशक टीसीपी संदीप कुमार टीसीपी पलानर सतीश शर्मा ने राज्यपाल को घुटी पिलाने की खूब कोशिश की।

राज्यपाल ने नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 के बारे में परामर्श दिया कि अधिकारी वर्ग यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में अवैध निर्माण न हो क्योंकि भूकम्प की दृष्टि से हमारा राज्य संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला इमारतें जो भूकम्प की दृष्टि तथा संरचनात्मकता से असुरक्षित हैं, उनका संरचनात्मक परीक्षण करना अनिवार्य है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माणों को नियमित न करने वाले आदेशों का संज्ञान लेने को कहा।

इस बावत सुधीर शर्मा ने राज्यपाल को बताया कि सरकार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं कर रही है। उच्च न्यायालय ने रिटेंशन पॉलिसी न लाने की बात की है जबकि विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम में संशोधन द्वारा डेवियेशंस को नियमित करने के लिए विधेयक पास किया है और ये एक वर्ष तक ही लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने इसी तरह के विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों का हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि विभाग ने अवलोकन किया है उसके बाद ही यह संशोधन लाया गया है।

सुधीर शर्मा को कहना पड़ा कि सभी भवन जों नियमतिकरण के लिए आएंगे उन सभी का संरचनात्मक परीक्षण करवाया जायेगा, जिसके लिए विभाग ने संरचना से जुड़े अभियन्ताओं तथा इससे सम्बन्धित संस्थाओं को पंजीकृत करना शुरू किया है।

मंत्री ने राज्यपाल को यह भी विश्वास दिलाया कि भविष्य में लोग नियमानुसार ही निर्माण करें इसके लिए विभाग ने आर्नलाईन एप्लिकेशन, ऑनेलाईन ट्रैकिंग तथा बिजली एवं पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रावधान कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त विभाग ने निजी व्यवसायिकों की देखरेख में निर्माण कार्य करने तथा अनुमति प्रदान करने हेतु नीति बनाई है जिसे सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

बावजूद इसके राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 पर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अभी ये भरोसा नहीं दिया कि वो इसे साइन कर ही देंगे।

बागवानों को लाभान्वित करने के लिये ऋण प्रक्रिया सरल बनाएं: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मण्डल की 379वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बागवानों के लिए ऋण की प्रक्रिया

काफी उदार होनी चाहिए। बागवान चाहे ऋण खेती, उपकरण अथवा सिंचाई उद्देश्य के लिए ले रहे हों, इन्हें लाभान्वित करने के लिये प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा मानकों को उदार बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सहकारी बैंक, विशेषकर किसानों व बागवानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं अपनाकर बैंक की उन्नति एवं विकास की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहा है, जो ग्रामीण लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के बागवानी क्षेत्र पर आधारित दस्तावेज 'स्टेट्स एंड रिपोर्ट' का भी विमोचन किया।

हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने निदेशक मण्डल के निदेशकों सहित मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 लाख रुपये का चेक तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सरकार को देय 7,21,920 रुपये के लाभांश का चेक भी भेंट किया।

हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री द्वारा बैंक को पूर्ण समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने अवगत करवाया कि बैंक द्वारा राज्य में 21 नई शाखाएं तथा दो विस्तार कांउटर खोलने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा बैंक को 'ए' पर्यवेक्षी का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि शाखाओं के विस्तार तथा सभी प्रकार की आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के कारण पिछले कुछ वर्षो के दौरान बैंक के लाभांश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने एनपीए में 11.20 प्रतिशत की कमी को 30 सितम्बर, 2016 तक 5.74 प्रतिशत तक लाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

प्रबन्धक निदेशक गोपाल शर्मा ने इस अवसर पर पावर प्वांइट प्रस्तुति के माध्यम से बैंक के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला।

मुख्य सचिव वी.सी. फारका, राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष पितामबर दास नेगी, निदेशक मण्डल के सदस्य केशव नायक, दिनेश कुमार शर्मा, भारत भूषण, राम सिंह चम्बयाल, सुभाष चंद शर्मा, नरेश चौहान, पंडित शिव लाल, टी.एस. राणा, गौरजा शर्मा, अजीत पाल महाजन, दीवान शर्मा, इकबाल मोहम्मद, बहादुर सिंह ठाकुर तथा मोहन मेहता सहित बैंक और नाबार्ड के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे

अनुराग ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन से की मुलाकात

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से भोजन पर आमंत्रित किया था। हिमाचल प्रदेश-सांसद, हमीरपुर और बीसीसीआई एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री जॉन की से मुलाकात की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम फिलहाल भारत के दौरे पर है और पांच मैचों की वन-डे इंटरनेशनल (वनडे) श्रृंखला खेल रही है। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और एक सक्रिय सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विशेष लंच में आमंत्रित किया गया था। इस पर टिप्पणी करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, यह मेरे लिए एक सम्मान की बात थी की प्रधानमंत्री ने मुझे इस विशेष लंच पर आमंत्रित किया और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जॉन की के साथ बातचीत काफी सकारात्मक थी और उनके साथ इस प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होना एक सम्मान की बात है।

विधान सभा सचिवालय में सामान्य विकास समिति की बैठकें आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय में 25 व 26 अक्तूबर, 2016 को सामान्य विकास समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय सभापति सुरेश भारद्वाज द्वारा की गई। इन बैठकों में सदस्यों खूब राम, गोबिन्द राम शर्मा, विक्रम सिंह जरयाल, संजय रतन, किशोरी लाल व अनिरूद्ध सिंह ने भाग लिया। समिति ने अपनी इन बैठकों में पर्यटन तथा परिवहन विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं/कार्यो तथा इनसे सम्बन्धित आश्वासनों पर प्राप्त विभागीय उत्तरों की समीक्षा की तथा कुछ विभागीय उत्तरों पर अतिरिक्त एवं अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया।

चांशल घाटी को साहसिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाए:वीरभद्र सिंह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हि.प्र. पर्यटन विकास बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला शिमला के दूर-दराज क्षेत्र डोडरा-क्वार को जोड़ने वाली चांशल

घाटी में साहसिक गतिविधियों तथा चांशल (4520 मीटर) की ढलानों पर स्कींग शुरू करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री ने भारतीय पर्वतारोहण फेडरेशन की प्रस्तुति, जिसमें चांशल तथा इसके आस-पास ट्रैकिंग, पैराग्लाईडिंग, रीवर रॉफ्टिंग तथा स्कींग की अपार संभावनाओं को दर्शाया गया, को देखने के उपरांत कहा कि चांशल घाटी में कई किलोमीटर तक फैले ऐसे खुले हरे मैदान हैं, जो स्कींग एवं अन्य गतिविधियों के लिये उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि यहां कुछ छोटी झीलें तथा किन्नौर जिले की सांगला घाटी, रामपुर व उत्तराखण्ड को जोड़ते हुए एक दर्जन से अधिक बर्फ से ढके ट्रेकिंग मार्ग हैं, जहां साहसिक खेल प्रेमियों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और भी बहुत कुछ हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3978 मीटर ऊंचे रोहतांग दर्रे के मुकाबले चांशल घाटी में आगन्तुकों के लिये बहुत कुछ है और अन्य सुविधाओं सहित इस क्षेत्र में सड़क नेटवर्क में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में कुछ रज्जू मार्ग परियोजनाओं के लिये छूट प्रदान करने पर भी चर्चा की गई। इन रज्जू मार्गों के लिये अनेक बार निविदाएं आमंत्रित करने के बावजूद कोई भी उपयुक्त अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं हुई। इन परियोजनाओं में टोबा से नयना देवी, शाहतलाई से दियोट सिद्ध, न्यूगल से पालमपुर तथा सराहन से बशाल कण्डा शामिल हैं।

बैठक के दौरान पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये पटे पर देने के बजाए बद्दी में एडवेंचर पार्क अथवा गोल्फ कोर्स विकसित करने के सुझाव आए। इसी प्रकार झटिंगरी (मण्डी), कुल्लू जिला के बंजार में शोझा तथा सिरमौर जिला के सुकेती को विकसित करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बोली मानदण्डों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।

यह भी अवगत करवाया गया कि हि.प्र. अधोसंरचना विकास गोर्ड के माध्यम से विभाग रज्जू मार्ग परियोजनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया में लगा है, जिनमें 150 करोड़ रुपये की धर्मशाला से मैकलोडगंज परियोजना, जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, आदी हिमानी से चामुण्डा तक 5.80 किलोमीटर रज्जू मार्ग परियोजना, जिसके सरेखण एवं सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया जा चुका है, 8.63 किलोमीटर पलचान से रोहतांग रज्जू मार्ग परियोजना तथा भुंतर से बिजली-महादेव रज्जू मार्ग परियोजना जिसके लिए बोली स्वीकार कर ली गई है और अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए औपचारिकताओं की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू, मण्डी, चिंतपूर्णी, नाहन, ऊना, हमीरपुर तथा ढली (शिमला) बस अड्डों के सुधार के निर्देश जारी किए। गत बैठक में परिवहन विभाग को इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था, जो ढली बस अड्डे में सुधार के सम्बन्ध में अभी भी प्रतिक्षित है।

बोर्ड ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली फिल्में बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की, जिसके लिए आरम्भ में 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है तथा इसकी निविदाओं को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले में सपनी किले के जीर्णोद्धार एवं बहाली कार्य को एक मुश्त पूरा करने का सुझाव दिया। शिमला जिले पन्द्रह-बीश क्षेत्र के सरपारा में नौ-नाग झील के विकास एवं सौंदर्यीकरण तथा शिमला शहर में वर्षा शालिका एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को धनराशि प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कांगड़ा की तर्ज पर पौंग डैम परिसर में किसी भी स्थान पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

हि.प्र. पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष विजय सिंह मनकोटिया ने पौंग डैम में पर्यटन गतिविधियों में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पौंग बांध में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए राज्य सरकार के साथ भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड से बैठक करने का अनेक बार आग्रह करने के बाबजूद बीबीएमबी अधिकारी मंद दृष्टिकोण अपना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व बीबीएमबी को स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने हवाई अड्डे के विकास और शिमला के लिए उड़ानों पर चिंता जाहिर की। कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव अनुराधा ठाकुर ने शिमला जिला में ब्रिटिशकाल के चूरट एवं गुम्मा में जल धरोहर संग्रहालयों के विकास का सुझाव दिया, जो अभी भी क्रियाशील हैं।

हिमाचल प्रदेश देश का प्रथम 'बाह्य शौचमुक्त' राज्य घोषित

शिमला/शैल। 'स्वच्छ भारत मिशन' के उद्देश्य को पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में देश का पहला बाह्य शौचमुक्त राज्य घोषित किया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह होटल पीटरहॉफ में आयोजित एक समारोह में पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को देश का पहला पूर्णत बाह्य शौचमुक्त राज्य घोषित करने पर गौरवान्वित दिखाई दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा तथा भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से परमेश्वरन अय्यर भी शामिल हुए। समारोह का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य में इस उपलब्धि को हासिल करने के राज्य सरकार के मिशन में सहयोग के लिए लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था।

समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि हालांकि सिक्किम राज्य बाह्य शौचमुक्त बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य है, लेकिन यह छोटे राज्यों की श्रेणी में हैं। उन्होंने कहा कि केरल राज्य बाह्य शौचमुक्त राज्य घोषित होने की दौड़ में शामिल है लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने केरल को पछाड़ते हुए बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि केरल को 4 दिनों के उपरांत पहली नवम्बर को 'केरल दिवस' के अवसर पर बाह्य शौचमुक्त घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय ग्रामीण मंत्री से उनके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही चाहते थे कि हमारा राज्य बड़े राज्यों में सबसे पहले बाह्य शौचमुक्त बने। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमने इस उपलब्धि को निर्धारित तिथि मार्च 2016 से पूर्व हासिल कर लिया और हम भविष्य में भी इस स्थान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि इस अभियान को जारी रखना अब अधिक महत्वपूर्ण है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता बनाए रखने पर हमेशा ही जोर देते हुए कहा था कि ईश्वरभक्ति तथा आजादी के बाद हमारे लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के लिए लोगों के जीवन में स्वच्छता का पैमाना उनके शौचालयों की स्थिति था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य केन्द्रीय वित्त पोषित विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करता है और हमेशा करेगा। उन्होंने कहा कि देश एक है और इसे विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार राज्य के लोगों के कल्याण के लिए केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी हिमाचल को बाह्य शौचमुक्त बनाने की पहल एवं सोच के लिए राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही ठोस एवं तरल कूड़ा कचरा प्रबन्ध के निदान में भी अग्रणी बनेगा। उन्होंने हिमाचल को सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य बनाने तथा जैव निस्तारण तकनीक अपनाकर सामुदायिक भागीदारी से संचालित संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी।

इस अवसर पर बोलते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की उपस्थिति में निर्धारित समय सीमा से 6 माह पहले इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए राज्य को बधाई दी।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किए गए व्यापक अभियान की सराहना करते हुए नड्डा ने कहा कि यह गौरव की बात है कि हिमाचल बड़े राज्यों की श्रेणी में बाह्य शौचमुक्त बनने वाला पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि अंतिम पड़ाव को पार करना बहुत मुश्किल कार्य है और उन्होंने राज्य सरकार के अभियान के तरीके की सराहना की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हिमाचल सरकार के अनुभवों तथा उनके द्वारा अपनाए गए स्थायी तंत्र को सांझा करेगी। उन्होंने निकट भविष्य में जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने की भी ईच्छा जताई। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ओंकार शर्मा ने इस अवसर पर जानकारी दी कि राज्य के सभी 12 जिले, 78 विकास खंड, 3226 पंचायतें तथा 18,465 गांव को बाह्य शौचमुक्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यक्रमों को संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 28 सितम्बर से 20 अक्तूबर, 2016 तक आवश्यक बल प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य को बाह्यशौचमुक्त बनाने की दिशा में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। मण्डलायुक्तों, समस्त उपायुक्तों तथा खण्ड विकास अधिकारियों, फील्ड राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान में गहन पहल के लिये प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के साथ सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान का ऑन-लाईन लोकार्पण किया।

वनाधिकार कानून प्रक्रिया तेज करने के लिये लिप्पा संघर्ष समिति के सदस्यों की राहुल गांधी से भेंट

शिमला/शैल। हिमालय नीति अभियान, हिम लोक जागृति मंच व एनवारोनिक्स ट्रस्ट का प्रतिनिधिमण्डल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी व पूर्व वन एंवम पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से हिमाचल प्रदेश में वनाधिकार कानून के कार्यान्वयन की स्थिति व प्रक्रिया को तेज करने के लिये मिला। प्रतिनिधिमण्डल में लिप्पा संघर्ष समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी का धन्यावाद किया कि पार्टी ने ग्राम सभा का वनाधिकार कानून के अनुसार ग्राम सभा पर विश्वास रखा व ग्राम सभा के अधिकार को सनिश्चित करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से HPPCL द्वारा दायर अपील को वापिस लिया जिसमे NGT ने ग्राम सभा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुये HPPCL की परियोजना के लिये भूमी हस्तांतरण के लिये वनाधिकार कानून के तहत ग्राम सभा से मजुरी लेने के बारे में कहा गया है। HPPCL ने अपनी अपील में कहा था कि ग्राम सभा के लोग अकुशल है व उपद्रवी लोग परियोजना के खिलॉफ काम कर रहे हैं। इसलिये ग्राम सभा से मंजूरी की शर्त को हटाया जाये।

लेकिन कानून की व ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष कर रही हिमालय नीति अभियान ने यह मुद्दा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संज्ञान मे लाया जिसे चर्चा उपरान्त ग्राम सभा व वनाधिकार कानून को लागू करने के लिये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आशवासन दिया था कि जल्द ही प्रदेश सरकार से इस बारे में चर्चा करने के उपरान्त ग्राम सभा के अधिकारों को बचाने के लिये प्रयास किया जायेगा तथा स्वरूप सरकार ने वनाधिकार के तहत ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायलय में HPPCL की अपील को वापिस लिया गया इसके लिये लिप्पा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का धन्यावाद किया।

प्रतिनिधिमण्डल ने इस बारे मे भी चर्चा की कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो दोनों ने ही यह बार-बार लिख कर दिया कि हिमाचल में वनाधिकार वन बन्दोवस्त के समय से ही दर्ज कर दिये है और अधिकारो को दोबारा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है जो कि सरासर गलत है क्योंकि वन बन्दोवस्त में लोगों को वनोपयोग के लिये कुछ छूट दे रखी है जो कि कानूनी रूप से अधिकार की श्रेणी में नहीं हैं अधिकारों को वास्तव में दर्ज करने के लिये कानून ही 2006 में बना है फिर वन बन्दोवस्त जो कि 19स्वीं व 20स्वी शताब्दी में हुये हैं अत: वन बन्दोवस्त मे लोगों के दबाव में ब्रिटिश हुकुमत ने कुछ छूटें दे रखी हैं जो आज भी छूट के नाम से है ना कि अधिकार के नाम से। अत: यह भी तय किया गया कि इस मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार से चर्चा की जायेगी और वनाधिकार कानून को लागू करने में स्थानीय समुदायों की मदद की जायेगी।

गुमान सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी व पूर्व वन एंवम पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को इस बात से भी अवगत करवाया कि वर्ष 2002 में हिमाचल की जनता को बेवकूफ बनाकर उस वक्त की सरकार ने यह वादा किया कि जिन भी लोगों का जंगल की जमीन पर दखल है वह जमीन उनके नाम कर दी जायेगी लेकिन यह मात्र जनता के साथ छलावा था लोगो ने जमीन को अपने नाम करने के लिये शपथ पत्र दिये लेकिन लोगों के नाम जमीन होना तो दूर उल्टा न्यायालय के ऐसे लोगों पर मुकदमा चला कर जमीन से बेदखली के आदेश दे दिये जो कि वनाधिकार कानून की धारा 4, 5 के विरुध है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भाग में अपनी भौगोलिक व जलवायु के कारण किसान कृषि व बागवानी करके साथ साथ जंगलों पर मुख्यता निर्भर हैं। जो हिमालय में भूमि सीमा की वजह से सहजीवी संशाधनों के उपयोग की बेहतरीन मिसाल है।

अत: उच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि से लोगों की बेदखली के खिलॉफ सरकार को लोगों के हितों को बचाते हुये याचिका दायर करनी चाहिये ताकि वन अधिकार कानून के प्रक्रिया को लागू किया जा सके। इस बारें मे भी उपाध्यक्ष ने आशवासन दिलाया कि वह सरकार से बात करेगें और जय राम रमेश के सहयोग से याचिक दायर करने के बारे में चर्चा की जायेगी।

गुमान सिंह ने यह भी बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हिमालय नीति अभियान की सहायता से वन अधिकार के सामुदायिक दावे किये गये है अत: दावो के निपटारे के लिये भी सरकार से चर्चा करनी चाहिये ताकि लोगों को उनके अधिकार मिल सके, उपाध्यक्ष ने इस बारे में भी कदम उठाने व लोगों के वनाधिकारों को जल्द से जल्द दिलवाने की प्रक्रिया के लिये चर्चा की जायेगी व ग्राम सभाओं को मजबूत करने व कानून को पूरी तरह से लागू करवाने के लिये पार्टी बचनवद्ध है यह जय राम रमेश ने आशवासन दिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वीरभद्र और सुक्खु में चल रहा शह-मात का खेल कहां रूकेगा

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के दो दिन तक चले जनरल हाऊस के बाद प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी ने पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए एलान किया है कि सुक्खु नहीं बदले जायेंगे और विधान सभा का अगला चुनाव वीरभद्र सिंह की ही कमान में लड़ा जायेगा। अंबिका सोनी के साथ ही सुक्खु ने भी यह कहा कि उनके वीरभद्र सिंह के साथ कोई मतभेद नही है। लेकिन अंबिका सोनी ने अपने ब्यान के साथ ही यह भी जोड़ा है कि उनके स्तर पर तो यही स्थिति है परन्तु उनसे ऊपर हाईकमान राहूल गांधी और सोनिया गांधी भी है जो कोई भी फैसला ले सकते हैं। अंबिका का यह कहना फिर सारी स्थिति को खुला छोड़ देता है। जनरल हाऊस में नेताओं ने जिस तरह से अपने विचार रखे हैं उनमें मुख्यमंत्री ने खुलकर संगठन की कार्यशैली पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमन्त्री ने स्पष्ट कहा कि संगठनात्मक जिलों के गठन से पूर्व उनसे राय नही ली गयी। अब यदि भाजपा प्रशासनिक जिले बनाने का वायदा कर देती है तो सरकार और पार्टी की फजीहत होगी। सचिवों की नियुक्तियों पर बहुत ज्यादा तलख थे। इस पर सुक्खु ने यहां तक कह दिया कि हर पिता पुत्र मोह का शिकार होता ही है। संगठन में सारे लोग चुनकर आये हैं। बाली ने कांग्रेस के आरोप पत्र पर कोई ठोस कारवाई न होने का मुद्दा उठाते हुए यहां तक कह दिया कि पार्टी लोकसभा की चारों सीटें क्यों और कैसे हार गयी। वरिष्ठ नेताओं के इस तरह के वक्तव्य पार्टी और सरकार के तालमेल की पूरी तस्वीर हैं।

वीरभद्र अपने बेटे को पूरी तरह स्थापित करने के लिये किसी भी हद तक जा सकते हैं यह जगजाहिर हो चुका है। इसी मंशा से उन्होने वीरभद्र ब्रिगेड को अब एक एन जी ओ की शक्ल दी है। ब्रिगेड और अब एन जी ओ प्रमुख बलदेव ठाकुर का सुक्खु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया जाना तथा सुक्खु के खिलाफ आये भाजपा के आरोपों पर मुख्यमन्त्री का तुरन्त जांच पडताल का एलान किया जाना इसी कडी के हिस्से माने जा रहे हैं। विक्रमादित्य का टिकट आंवटन के मामले में हाईकमान के दखल का विरोध करना भी यही प्रमाणित करता है। क्योंकि रोहडू विधान सभा चुनावों में एक बार वीरभद्र के पूरे प्रयासों के वाबजूद प्रतिभा सिंह को टिकट न मिल पाना वीरभद्र की आशंकाओं का ठोस आधार है। चुनावों में अपना एकछत्र वर्चस्व स्थापित करने के लिये पार्टी अध्यक्ष पर पूरा कब्जा होना आवश्यक है और सुक्खु के रहते यह संभव नही है। इसलिये सुक्खु के खिलाफ हर संभव मोर्चा खोला गया है।

अपनी मनवाने के खेल में वीरभद्र किस हद तक जा सकते हैं इसका गवाह 1980-81 में जनता पार्टी के दल बदल से सरकार बनाये जाने का विरोध 1993 में पंडित सुखराम के विरोध के लिये विधानसभा भवन के घेराव की नौवत आना और 2012 में शरद पवार के साथ जाने की अटकलों का गर्म होना रहा है। फिर इस बार तो सीबीआई और ईडी जांच के परिणामों की आशंका बनी हुई है। ऊपर से हाईकमान स्वंय भी कमजोर मानी जा रही है। इस परिदृश्य में थोडे से तल्व तेवर दिखाकर पार्टी पर कब्जा करना आसान माना जा रहा है।

पार्टी और सरकार के बीच इस तरह की वस्तुस्थिति का होना जगजाहिर है। लेकिन इसके वाबजूद अगला चुनाव वीरभद्र के ही नेतृत्व में लड़ा जाना और सरकार की वापसी के दावे किये जाना चर्चा का विषय बन रहे हैं। 2017 के अन्त में विधानसभा चुनाव होने है परन्तु समय पूर्व ही चुनाव हो जाने की संभावनाएं भी बनी हुई है। ऐसे में यह समय चुनावी गणित के साये में देखा जा रहा है। लेकिन इस जनरल हाऊस के लिये आयी पार्टी प्रभारी अंबिका सोनी के स्वागत के लिये कोई बड़ा उत्साह नही देखा गया जबकि सामान्यत: ऐसे मौकों पर खूब ढोल नगाडे बजते थे। चुनावों में टिकटों की दावेदारीयों के लिये संभावित उम्मीदवारो के समर्थको का भारी हजूम रहता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नही मिला। पार्टी कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों बल्कि विवादित बनाये गये पार्टी सचिवों के अतिरिक्त प्रभारी को मिलने कोई नही पहुंचा। इसी तरह पीटरहॉफ में भी सरकार में विभिन्न निगमों/बार्डो में ताज पोशीयां पाने वालों से हटकर और कोई मिलने वाला नही था। प्रभारी दोनों दिन करीब दो-दो घण्टे लगभग खाली रही। पीटरहॉफ में लंच के समय मुख्यमन्त्री के पास कोई भीड़ नही थी। पार्टी के भीतर की यह स्थिति अपने में ही बहुत कुछ कह जाती है। इस पर मुख्यमन्त्री और पार्टी अध्यक्ष में चल रहा शह और मात का खेल क्या गुल खिलाता है इस पर सबकी नजरें लगी हुई है।

जिला परिषद शिमला की बैठक के बाद प्रदेश का खुला शौच मुक्त होने का दावा सवालों में

शिमला/ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश ने खुला शौच मुक्त राज्य होने का लक्ष्य तय समय सीमा से पांच माह पहले ही पूरा कर लिया है। इसमें देश के बड़े राज्यों में यह मुकाम हासिल करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। यह दावा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने होटल पीटर हाफ में इस उपलक्ष में आयोजित एक समारोह में केन्द्रिय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में किया है। सरकार के इस दावे से हिमाचल विश्व बैंक से स्वच्छता प्रौजैक्ट के लिये स्वीकुत नौ हजार करोड़ की सहायता पाने में भी भागीदारी बन गया है यह एलान ग्रामीण विकास मन्त्री तोमर ने किया है।

सरकार की इस तरह की उपलब्धियां प्रशासन द्वारा जुटाये आंकड़ों पर आधारित रहती हैं। खुला शौच मुक्त होने का दावा भी ऐसे ही आंकड़ों के आधार पर किया गया है। लेकिन यह दावा कितना सही है इसका खुलासा जिला परिषद शिमला की हुई बैठक से हो जाता है। इस बैठक में जिला के कोटखाई वार्ड की सदस्य नीलम सरकेक ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड के एक भी स्कूल मे शौचालयों का निर्माण नही हुआ है और ऐसे में सम्मपूर्ण खुला शौच मुक्त्ता का दावा कैसे किया जा सकता है। नीलम के इस आरोप से बैठक में हड़कंप मच गया। तुरन्त जिलाधीश और दूसरे संवद्ध अधिकारियों ने उतेजित सदस्य को शांत करने के लिये यकीन दिलाया कि इन स्कूलों के लिये आज ही धन का आवंटन कर दिया गया है। जिला परिषद की बैठक में जिस तरह से महिला सदस्य ने अपने वार्ड की व्यवहारिक स्थिति रखी उससे यह सवाल उठता है कि जिला प्रशासन के पास जव यह जानकारी थी कि उस वार्ड के स्कूलों मे अभी शौचालय का निर्माण नही हो पाया है तो उन्होने इसकी जानकारी सरकार को क्यों नही दी। सदस्य के शोर मचाने पर इसके लिये धन आवंटन किया जाता है। यक निर्दलीय सदस्य इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिये चुनावी चुनौती बनती जा रही है। संभवत: इसी कारण से इसके वार्ड में ऐसा हुआ है। लेकिन इससे पूरे प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी अभी तक ऐसी स्थितियां होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

सीबीआई ने विजिलैन्स

.....पृष्ठ 1 का शेष

जाती है। लेकिन बाद में यह सारे प्रौजेक्ट अधूरे पाये जाते हैं। और इनकी लागत कई गुणा बढ़ जाती है। इससे केन्द्र को भेजे गये सारे प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यह प्रश्न चिन्ह लगाना केन्द्र के धन का सीधा दुरूपयोग बन जाता है। गोयल के मुताबिक पर्यटन में केन्द्र के करीब दस करोड़ के दुरूपयोग के दस्तावेजी प्रमाण उन्होने शिकायतों के साथ भेजे हैं। केन्द्र के धन के इस तरह के दुरूपयोग का कड़ा संज्ञान लेते हुए सीबीआई ने इसकी जांच विजिलैन्स को भेजी है। अब वीरभद्र की विजिलैन्स गोयल की इन शिकायतों पर कितनी और क्या कारवाई करती है। इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है क्योंकि पर्यटन मन्त्री मुख्य मन्त्री स्वयं है और मुख्यसचिव ही पर्यटन सचिव भी हैं। गोयल ने दावा किया है कि इन शिकायतों को ठीक अंजाम तक पहुंचाने के लिये वह हर लड़ाई लड़ने के लिय तैयार हैं। इस संद्धर्भ में उसने सभी संवंद्ध अदारों से आरटीआई के तहत उसकी शिकायतों पर हुई कारवाई की जानकारी भी मांग रखी है। जिन अधिकारियों के खिलाफ गोयल की शिकायतें है वह सब मुख्यमन्त्री के अतिविश्वस्तों में गिने जाते हैं। मामला केन्द्र के धन का है। जिसके लिये अधिकारियों पर झूठे उपयोगिता प्रमाण पत्र सौपने का आरोप है।

विजीलेंस जांच हो मनकोटिया की संपति की जोगटा गुट का निशाना

शिमला/ब्यूरो। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एसएस जोगटा ग्रुप ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से महासंघ के सुरेंद्र मनकोटिया गुट के कर्मचारी नेताओं की संपति की जांच करने की मांग की है। महासंघ के महासचिव हेम सिंह ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान ठाकुर अतिरिक्त महासचिव त्रिलोक ठाकुर समेत पूरी कार्यकारणी ने कहा है कि महासंघ ने सुरेंद्र मनकोटिया और उनके साथियों की ओर से अर्जित संपति की जांच को लेकर विजीलेंस और मुख्यमंत्री को शिकायत दी हुई है। इस शिकायत पर तुरंत जांच शुरू कराई जाए। इन नेताओं ने साथ ही सरकार से मांग की कि उन्हें मान्यता प्रदान करने और उनके साथ जेसीसी की बैठक करने की मांग की है। महासंघ के सुरेंद्र मनकोटिया गुट पर सरकार की आखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है।

इन कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सुरेंद्र मनकोटिया गुट के लोग भाजपा के समर्थक रहे हैं और पूर्व की धूमल सरकार में कर्मचारियों का उत्पीड़न करते रहे हैं। इस गुट के साथ पूर्व मुख्यमंत्रे प्रेम कुमार धूमल का ड्राइवर शांतिस्वरूप शर्मा कंधे से कंधा मिलाते हुए चल रहा है। सुरेंद्र मनकोटिया के मुख्य सलाहकार हरीश कुमार पूर्व धूमल सरकार के हितेशी राम सिंह गुट का सलाहकार रह चुका है। जबकि सुनीता सुरेन्द्र ठाकुर की शिमला जिला की क्षेत्रीय सचिव थी। इन नेताओं ने कहा कि इन स्वयंभू कर्मचारी नेताओं ने बेनामी संपतियां एकत्रित करने के लिए संगठन का इस्तेमाल किया।

क्रशन पर इस्तीफा मांगने

.....पृष्ठ 1 का शेष

जमीन पर न उतरने का ठिकरा वीरभद्र सिंह सरकार पर फोड़ दिया। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार को कामों में तेजी दिखानी चाहिए।

उन्होने कहा कि देश के 40 करोड़ कमजोर तबके के लोगों का अगले साल से एक लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। उन्होने दावा किया कि जनधन योजना के तहत अब तक 38 हजार करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो चुका है। उन्होने कहा कि जब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार सत्ता में रही है हिमाचल के लिए खास पैकेज मिले हैं। भाजपा ने कई पहलें की। नड्डा ने ये भी एलान किया कि अगले साल से देश में 15 हजार डाक्टरों की पीजी की सीटें बढ़ाई जाएंगी।

इसके बाद नड्डा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलने आईजीएमसी पहुंचे। यहां ये उल्लेखनीय है कि मोदी के मंत्री नड्डा व वीरभद्र सिंह के बीच गहरे दोस्ताना रिश्ते हैं। वीरभद्र सिंह व प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी दोस्ताना रिश्ते हैं।

नडडा ने प्रेस क्लब शिमला को 11 लाख रुपए देने का भी एलान किया।